वस्त्र मंत्रालय

<u>मंत्रिमंडल के लिए मई, 2019 का मासिक सारांश</u>

1. <u>नीतिगत निर्णय</u>

i. वर्ष 2018-19 मौसम के लिए कच्ची पटसन और मेस्टा की अंतिम आपूर्ति मांग के परिदृश्य की समीक्षा करने और वर्ष 2019-20 के मौसम में नई फसल के उत्पादन की संभावनाओं का आकलन करने के लिए पटसन सलाहकार बोर्ड (जेएबी) की बैठक सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

ii. स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठक दिनांक 30.05.2019 को आयोजित की गई थी और राज्य सरकार की 18 एजेंसीयां और वस्त्र मंत्रालय के क्षेत्रीय डिवीजन को 1,20,440 के प्रशिक्षण लक्ष्य की सिफारिश की गई थी।

2. <u>महत्वपूर्ण उपलब्धियां</u>:-

i. **<u>हथकरघा क्षेत्र</u>**: बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को 6% के रियायती ब्याज दर पर ऋण, 10,000/- रुपए प्रति बुनकर की दर से मार्जिन मनी और 3 वर्ष के लिए ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 964.89 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण की राशि में से वर्ष 2014-2015 से लेकर अब तक 2,34,224 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 724.18 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है।

ii. **<u>हस्तशिल्प क्षेत्र:</u>**

क) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम

i. स्टॉकहोम, स्वीडन में दिनांक 25 मई, 2019 से एक तीन दिवसीय पर्व **'नमस्ते स्टॉकहोम'** का आयोजन किया गया और इस पर्व में 5 पुरस्कार विजेता कारीगरों ने भाग लिया। 20,000 लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्टॉकहोम में भारत के राजदूत द्वारा किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान 4 लाख रुपए से अधिक की बिक्री की गई।

ii. यिवू चाइना में दिनांक 23-26 मई, 2019 से आयोजन स्थल पर हस्तशिल्प एक प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ओडिशा के राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र धारक कारीगरों ने भाग लिया।

ख) घरेलू कार्यक्रम

देश भर में दिनांक 29.05.2019 से 04.06.2019 तक 24 विशेष विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों लगभग 1000 कारीगरों के भाग लेने की संभावना थी।

iii. **<u>कपास:</u>** मई, 2019 के दौरान कपास बीज की अखिल भारत स्तर पर आवक 16.83 लाख गांठ थी। चूंकि कपास का बाजार मूल्य सभी कपास उत्पादक राज्यों समर्थन मूल्य से अधिक चल रहा था इसलिए भारतीय कपास निगम ने एमएसपी अभियान के अंतर्गत कपास बीज की खरीद नहीं की।

iv. **<u>प्रौद्योगिकी उन्नयन:</u>** संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) के अंतर्गत मई, 2019 के दौरान 4.82 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 0.42 करोड़ रुपए की सब्सिडी की आवश्यकता के साथ एक यूआईडी जारी किया गया है।

v. **<u>विद्युतकरघा क्षेत्र:</u>** विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना के अंतर्गत 56,04,228 रुपए के प्रीमियम की भारत सरकार की हिस्सेदारी के साथ मई, 2019 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 37,526 विद्युतकरघा कामगार पंजीकृत किए गए।

3. ई-गवर्नेंस- वर्तमान में ई-फाइल प्रबंधन प्रणाली, कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली, छुट्टी प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे विभिन्न कार्यालय संबंधी मामलों के लिए मंत्रालय में ई-ऑफिस मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, मंत्रालय में पीएफएमएस-कर्मचारी सूचना प्रणाली का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें सभी भुगतान, जीपीएफ, आयकर आदि से संबंधित सूचना शामिल थी।

4. गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों पर सूचना

(i) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर (एनईएसएसी), शिलांग के सहयोग से एसआईएलकेएस (रेशम उत्पादन सूचना लिंकेज ज्ञान प्रणाली) विकसित की गई है और देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। 'एसआईएलकेएस' योजना निर्माताओं, फील्ड स्टाफ और रेशम उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एकल खिड़की, आईसीटी (सूचना और संचार

प्रौद्योगिकी) आधारित सूचना और सलाहकार सेवा प्रणाली है। परियोजना के प्रथम चरण में 24 राज्यों के कुल 108 जिले शामिल किए गए थे और दूसरे चरण में 70 जिलों को शामिल किया जा रहा है। गुवाहाटी, असम में हाल ही में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान चयनित 20 जिलों के लिए रेशम उत्पादन विकास (चरण-।।:पूर्वोत्तर राज्य) के लिए 'प्रोजेक्ट एटलस' और सिल्क पोर्टल की शुरूआत की गई थी। शेष 50 जिलों (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा) का अध्ययन किया जा रहा है।

(ii) केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने भी उपकरण अर्थात 'नवशेयर', एक स्वत: स्पष्ट गगन समर्थित ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) डाटा रिकॉर्डर का प्रयोग करके विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सहायता से सीएसबी और राज्यों द्वारा सृजित की गई एसेस्ट्स (पौध रोपण और अवसंरचना) की जियोटैगिंग में एनईएसएसी, शिलांग, मेघालय के साथ एक सहयोग पूर्ण परियोजना की शुरूआत की है। एस्सेट्स (पौध रोपण और अवसंरचना) की जियोटैगिंग के लिए एक मोबाइल एप अर्थात 'सिल्क्स' भी विकसित किया गया है। एनईएसएसी और सीएसबी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एसेस्ट्स की जियोटैगिंग पर पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य एवं सीएसबी अधिकारियों/वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के प्रक्रियाधीन है।